वैगन इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण

4342. **श्री ओंकार सिंह लखावत**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे, वैगन इंडिया लिमिटेड को वैगन बनाने के लिए सामवी प्रदान करता है;

(ख) वैगन इंडिया लिमिटेड, वैगनों के निर्माण के लिए श्रम पर कितने प्रतिशत व्यय करता है और इस संबंध में संस्थापन व्यय कितने प्रतिशत हैं; और

(ग) वैगन इंडिया लिमिटेड को रेलवे वैगनों के निर्माण पर सामग्री और श्रम संबंधी कितनी-कितनी लागत आती है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) वैगन इंडिया लिमिटेड एक आपूर्ति करने वाली कंपनी है जो कि रेलवे से वैगनों के आदेश प्राप्त कर अपने शेयर धारक सदस्य कंपनियों को वितरण करती है। यह रेलवे से कोई सामग्री प्राप्त नहीं करती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैगन इंडिया लिमिटेड द्वारा वैगनों का निर्माण किया जाना

4343. **श्री ओंकार सिंह लखावत**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैगन इंडिया लिमिटेड की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है;

(ख) वैगन इंडिया लिमिटेड में कितने अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं और वर्ष 1997-98 में उन पर कितना संस्थापन व्यय किया गया; और

(ग) क्या वैगन इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए रेलवे वैगनों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है; यदि हां, तो लक्ष्य क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) वैगन इंडिया लिमिटेड की स्थापना करने का एक मात्र उद्देश्य रेलवे से मुख्य रुप से वैगन के आदेश प्राप्त करना और जो इसके शेयर होल्डर हैं, को समान रुप से वैगन के निर्माताओं को वितरित करना था।

(ख) इस समय वैगन इंडिया लिमिटेड में 6 अधिकारी और 7 अन्य कर्मचारी हैं। अंपनी ने 1997-98 के दौरान कुल 43.16 लाख रुपये खर्च किए थे।

(ग) चूंकि वैगन इंडिया लिमिटेड वैगन उद्योग के लिए एक सर्विस संगठन है और वैगनों का निर्माण नहीं करती है इसलिए 1998-99 के दौरान डब्ल्यू आई एल द्वारा वैगनों के निर्माण को जारी रखने का प्रश्न नहीं उठता।

आयात नीति का उदारीकरण

4344. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयात नीति को और उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनके मामले में आयात नीति को उदार बनाया गया है;

(ग) इस आयात नीति का घरेलू लघु तथा कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पडेगा;

(घ) क्या इस आयात नीति के परिणामस्वरुप उपर्युक्त घरेलू उद्योग पनपेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो किस तरह और यदि इन्हें धक्का पहुंचता है तो इसी स्थिति में इन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने 13.4.1998 को 340 और मदों का निःशुल्क आयात करने की अनुमति दे दी है।

(ग) और (घ) निःशुल्क आयात सूची में पिरवर्तित की गई 340 मदों में से केवल 57 मदें ही लघु उद्योग से संबंधित है जो या तो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उनका विनिर्माण आरक्षित होने अथवा मजबूत लघु उद्योग उत्पाद आधार के कारण है। इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित 57 मदों में से 50 मदें हस्तातरणीय विशेष आयात लाइसेंसों के प्रति पहले ही आयात न्योग्य थी।

उदारीकृत आयात नीति का परिणाम लघु क्षेत्र में बनायी जाने वाली अनेक मर्दों के लिए कच्चे माल इत्यादि की सरलता से उपलब्धता के रुप में सामने आयेगा। और इसके फ्लस्वरुप, लधु एककों को अपनी उत्पादकता और उत्पाद गुणवत्ता में सुधार के रुप में लाभ पहुंचेगा। इसके कारण अधिक उत्पादकता प्राप्त करने हेतु निपुणता भी हासिल होगी।

(ङ) इन आयातों पर 5 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक (मूल) सीमा शुल्क लगाने से इन उद्योगों को आवश्यकतानुसार, सुरक्षा होती है।

Sick PSUs in West Bengal

4345. SHRJ GURUDAS DASGUPTA: Will the Minrster of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what a^e the Central Public Sector Undertakings which have fallen sick in West Bengal; and